भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

पत्र क्रमाक–3 / 2014 **03 अप्रैल, 2014**

फर्जी लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का आव्हान

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत देश की तमाम जनता का आव्हान करती है कि वह आगामी 16वें लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करें क्योंकि वर्तमान में जो लोकतंत्र अमल में है, यह फर्जी है। दरअसल यह देश के शोषक–शासक वर्गो का लूट तंत्र और दमन तंत्र है। हमारी पार्टी संघर्ष इलाकों की जनता का आव्हान करती है कि वह जन विरोधी, दमनकारी, देशद्रोही व फासीवादी कांग्रेस और भाजापा को मार भगायें और गांवों में घुसने मत दें। वोट मांगने आने वाली अन्य तमाम पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करें। गांवों पर हमलों, अवैध गिरफ्तारियों, फर्जी मुठभेड़ों, नरसंहारों आदि राज्य दमन, विस्थापन एवं जन हित के अन्य मुद्दों पर उनके रूख के बारे में सवाल करें व जवाब मांगे! चुनावी राजनीति को छोड़कर जन संघर्षो की मद्द में ही गांवों में घुसने की समझाइश देकर भेज दें।

देश के लुटेरे शासक वर्गों–सामंती, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग व उनके साम्राज्यवादी आकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र–राज्य सरकारों के द्वारा लोकतंत्र के नाम पर देश के चार उत्पीड़ित वर्गो–मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति व देशी पूंजीपति की बहुसंख्यक जनता की लूट, दमन, शोषण व शासन जारी है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में शोषक–शासक वर्गो की राजसत्ता को उखाड़ फेंककर शोषित–शासित जनता की असली जनवादी राजसत्ता की स्थापना के लिए क्रांतिकारी जनयुद्ध जारी है। दण्डकारण्य सहित देश के विभिन्न इलाकों में असली आजादी, असली लोकतंत्र एवं स्वावलंबन पर आधारित असली विकास के रास्ते में क्रांतिकारी जनताना सरकारों का गठन किया जा रहा है। दंडकारण्य मं गांव, एरिया, डिविजन स्तरों पर ये सरकारें काम कर रहे हैं। शोषक–शासक वर्गो के झूठे लोकतंत्र का सही व एकमात्र विकल्प ये ही हैं। ये जन राजसत्ता के अंग ही सही मायने में–रूप व सार में जनता के जनवाद को अमल करेंगे। दण्डकारण्य की जनता को चाहिए कि वह इन्हें मजबूत करें व फैला दें। देश की जनता से हम अपील करते हैं कि वह इन नई जन राजसत्ता के अंगों के बारे में जाने व समझें। देशव्यापी क्रांतिकारी जनयुद्ध में शामिल होवें और इस नये विकल्प को अमल में लाने के काम में आगे बढ़े।

दरअसल 1947 में जो आजादी मिली थी, वह झूठी व नाममात्र की है। अंग्रेजों से मिलीभगत करके देश की आजादी के साथ गद्दारी करने वाले भारत के दलाल बड़े पूंजीपति व सामांतियों को सत्ता हस्तांतरण हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्यवादियों को मार भगाने की लड़ाई की बजाय उनके साथ सांठगांठ करके भारत सरकार कानून, 1935 से लेकर 1946 तक शासन में हिस्सेदार बनते रहे। इसीलिए हमारी पार्टी यह मानती है कि 1952 से जारी संसदीय प्रणाली असल में संसदीय लोकतंत्र या बुर्जुआ लोकतंत्र ही नहीं है, यह फर्जी संसदीय लोकतंत्र है। आज की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था अर्ध–सामांती और अर्ध–औपनिवेशिक है। सामांती वर्ग, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग ही सही मायने में हमारे देश के शोषक–शासक वर्ग हैं। ये ही भारत की जनता के असली दुश्मन हैं। 1950 में भारत के संविधान के नाम पर जिसे अमल में लाया गया वह ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि कई युरोपीय देशों के संविधानों से लिये गये धाराओं का मिश्रण मात्र है। स्वंय संविधान निर्माता डॉ, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान सभा के बहुमत के दबाव में संविधान लिखा गया था। वास्तव में भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों व आदिवासियों व पिछडी जातियों के लिए बाबासाहेब की जिद में जोडे गये आरक्षण की सुविधा के सिवाय, उत्पीड़ित जनता के लिए कुछ भी नहीं है।

1952 से लेकर अब तक यानी 15वी लोकसभा तक इन चुनावों के जरिए इस देश पर शासन करने वाली पार्टियां चाहे कोई भी हो–सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही कांग्रेस या उसके गठबंधन वाली यू.पी.ए की पार्टियां हो या फिर भाजपा या उसके गठबंधन वाली एनडीए की पार्टियां हो सभी ने हमेशा जन विरोधी, देशद्रोही, दमनकारी, फासीवादी नीतियों पर ही अमल करती आयीं। जन भावनाओं, जन आन्दोलनों, किसान सशस्त्र संघर्षो के दबाव में संविधान की पीठिका में लिखी गयी बातों– संप्रभुता, धर्म निरपेक्षता, सामाजवादी गणतंत्र के ठीक विपरीत, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए काम करती आयीं।

देश के शोषक–शासक वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों ने देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है। धर्म निरपेक्षता की रट लगाते हुए हमेशा हिन्दू धार्मिक कट्टरता को ही हवा देती रहीं। धार्मिक अल्प संख्यकों– सिख, मुसलमान, ईसाइयों पर देश की कई जगहों में हमलों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि 1984 में सिखों के नरसंहार का कांग्रेस ने एवं गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का भाजपा ने प्रत्यक्ष नेतृत्व किया था।

भारतीय अर्थ व्यवस्था को साम्राज्यवादी अर्थ व्यवस्था की जंजीर की कड़ी के रूप में जोड़कर साम्राज्यवादी ताकतों के आर्थिक हितों के अनुरूप उसे डालने के लिए देश में जन विरोधी वैश्वीकरण–निजीकरण–उदारीकरण की नीतियों पर जोर–शोर से अमल करती आ रही हैं। साम्राज्यवादी लूट व विदेशी पूंजी निवेश के लिए देश के उद्योग–धंधों, खेती–बाड़ी व सेवा क्षेत्र के दरवाजों को खुला किया गया। इतना ही नहीं हाल के वर्षो में खुदरा व्यापार को भी कारपोरेट घरानों के हवाले किया गया है।

केंद्र–राज्य सरकारों की आर्थिक, औद्योगिक, खनन, कृषि नीतियां साफ तौर पर सामांती, बड़े औद्योगिक घरानों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हैं। विगत 5 सालों में उद्योगपतियों को करों में लाखों करोड़ रूपयों की छूट दी गयी। जबकि किसानों व मध्यम वर्ग के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडियों में भारी कटौती की गयी। जनता के पैसो से पूंजीपतियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर – एक्सप्रेस हाईवेज, फोरलेन सड़कें, पुल–पुलिया, मोबाइल टावरें, बड़े बांध, बैंक, थानें आदि का निर्माण जोरों पर है। विनिवेशीकरण के नाम पर लाखों करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। बड़ी खनन परियोजनाओं को जनधन से शुरू करके कच्चा माल सौंपते आये। अब तो खदानों को ही उन्हें सौंपा जा रहा है। बाल्को की माइनपाट खदान सहित दसियों हजार करोड़ की संपत्ति को महज 550 करोड़ में– कौड़ियों के भाव पूंजीपति अनिल अग्रवाल को सौंपा गया था। बड़े पूंजीपतियों के बड़े कारखानों, बड़े खदानों व उनके लिए जरूरी बिजली व पानी की आपूर्ति हेतु बड़े बांधों के निर्माण के लिए आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता के लाखों एकड़ की जमीन को छीना जा रहा है। सार्वजनिक हित के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों–5वीं अनुसूची, पेसा कानून आदि का खुला उल्लंघन करते हुए फर्जी व पुलिसिया ग्रामसभाओं का संचालन करते हुए ये सारे जन विरोधी कार्य किये जा रहे हैं।

देशी, विदेशी पूंजीपतियों के लिए जमीन से लेकर तमाम ढांचागत सुविधाओं के साथ 400 विशेष आर्थिक जोनों की मंजूरी दी गयी। हजारों एमओयू किये गये। इनकी शर्तें देश की जनता के लिए गोपनीय क्यों रखी गयी हैं? असल में ये शर्तें जन विरोधी हैं। देश के बड़े पूंजीपति व विदेशी पूंजीपति देश की संपदाओं को बेरोकटोक लूट रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम मंत्रालयों के घोटालों–आदर्श हाउसिंग एवं अन्य रक्षा घोटालों, 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला आदि में लाखों करोड जन धन को लूटा गया। यह लूट बरोकटोक जारी है। राजनेताओं, नौकरशाहों के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसके खिलाफ लोगों में व्याप्त आक्रोश व इससे उपजे आन्दोलन का फायदा उठाकर बनी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रही, चाहे कुछ ही दिनों के लिए क्यों न हो। वह भ्रष्टाचार मुक्त देश का भ्रामक प्रचार करते हुए देश में सत्तारूढ़ होने का सपना देख रहा है।

सरकारों की जन विरोधी नीतियों के चलते इस देश के शोषित–शासित व उत्पीड़ित वर्गो–मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ एवं देश पूंजीपति (छोटे व मध्यम) की जनता (देश की बहुसंख्यक जनता) का जीवन दिन ब दिन दूभर होता जा रहा है। काम के घंटों में बढ़ोत्तरी, वेतन भत्तों व रोजी–मजदूरी में कटौती, सरकारों की पूंजीपति परस्त व मजदूर विरोधी नीतियों, औद्योगिक सुरक्षा उपायों में जानबूझकर बरती जाने वाली अपराधिक लापरवाही, छंटनी, ले ऑफ, तालाबंदी, ठेकेदारी प्रथा, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के चलते मजदूरों खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत दयनीय बनी हुई है।

देश की कृषि को कारपोरेट संस्थाओं के लाभ के अनुकूल बदलने, खाद,बीज आदि के मामले में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियों में कटौती या बंद करना, सूदखोरों–बैकों के कर्ज व ब्याज का बोझ, लागत खर्च में बढ़ोत्तरी, सिंचाई का अभाव, अकाल व बाढ़, फसलों का उचित समर्थन मूल्य न मिलना आदि के चलते लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आत्महत्या की दर में छत्तीसगढ़ अव्वल है। कृषि प्रधान देश में अन्नदाताओं की आत्महत्याएं शासकों के किसान विरोधी व अपराधिक चरित्र का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। जोतने वाले को जमीन न मिलने, साल भर काम न मिलने की वजह से ग्रामीण इलाकों से भूमि हीन व गरीब किसान बड़ी तादाद में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। छग के गांवों से हर साल दिसंबर से जून के बीच 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण घर बार, बूढ़ों–बच्चों को छोड़कर काम की तलाश में जाते हैं जहां शोषण, लूट व अत्याचारों के शिकार होते हैं। केंद्र सरकार की बहुप्रचारित मनरेगा एवं अन्य योजनाओं, छत्तीसगढ़ सरकार की ढेरों झूठी सुधार योजनाओं की बस की बात नहीं है– पलायन को रोकना, गरीबी को दूर करना, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। क्यों कि ये सारी योजनाएं सिर्फ जनता को भरमाने के लिए हैं। एक तरफ मुठ्ठी भर लोगों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों की बेइंतहा लूट तो दूसरी ओर बहुसंख्यक गरीब जनता को इनसे वंचित रखा जाना जब तक जारी रहेगा, अमीर धरती के गरीब लोगों की यह विडंबना तब तक खत्म नहीं होगी। संसाधनों का इस्तेमाल समस्त जनता के हित में हो तभी यह विडंबना खत्म होगी। यह तभी संभव है जब उत्पीड़ित वर्गो– मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ व देशी बुर्जुआ क संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती हो और उसका तानाशाही कायम होती हो।

सरकारों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े औद्योगिक घरानों की अनुकूल आर्थिक नीतियों के चलते महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल की दरें लगातार बढ़ायी जा रही हैं जिससे तमाम अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इससे मजदूर–किसान व मध्यम वर्ग के लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व बैंक की शर्तो के तहत व्यवस्थापन खर्च को कम करने के नाम पर शिक्षकों व तमाम सरकारी विभागों के कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति पर देश भर की सरकारों ने पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिये हैं। शिक्षाकर्मी, शिक्षागारंटी , जन भागीदारी, संविदा नियुक्ति, कैजूअल कर्मचारी, दैनिक वेतन भेगी कर्मचारी आदि के नाम पर न्यूनतम वेतन व रोजी पर काम लिया जा रहा है। इससे शिक्षक व कर्मचारियों में न सिर्फ रोश है बल्कि हर साल अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकारों की ये कर्मचारी विरोधी नीतियां दरअसल अपने आकाओं को खुश करने के लिए ही है।

देश के सौ बड़े दलाल पूंजीपति घरानों की संपत्ति कुल जीडीपी का एक चौथाई है। सुनिल मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, आदि गोदरेज, शिव नाडार, पल्लोनजी मिस्त्री, अजीम प्रेमजी, दिलीप सांघवी, लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी– नौ बड़े उद्योगपतियों की कुल संपत्ति 672 हजार करोड़ रूपये हैं। देश के अरबपतियों की संपत्ति पिछले 15 सालों में 12 गुना बढ़ी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारों की नीतियां किसके अनुकूल हैं। गरीबों के उत्थान के नाम पर दिये जा रहे इंदिरा आवास के लिए 40 हजार रूपये जबकि मुकेश अंबानी निवासरत है, करीबन 1 हजार करोड़ के कीमती अंटेल्ला में।

देश के छोटे व मध्यम पूंजीपति भी सरकारों की बड़े पूंजीपति व बहुराष्ट्रीय कंपनी परस्त नीतियों के चलते दम घोंटू स्थिति में हैं। देश के करीबन 2 लाख से ज्यादा छोटे व मध्यम उद्योग बिजली, कच्चा माल की आपूर्ति के अभाव में बंद पड़े है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 7 सालों में पंजाब में 18,770 उद्योग बंद हो गये हैं। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा स्पंज आयरन

उद्योग सिर्फ लौह अयस्क व बिजली की आपूर्ति न होने के कारण बंद पड़े हैं। 5 से 6 हजार रूपये प्रति टन बाजार दर वाले लौह अयस्क को 500 रूपए प्रति टन के हिसाब से जापान व चीन को प्रति दिन दसियों हजार टन माल निर्यात करने वाली सरकार (एनएमडीसी) छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों की इस मांग को नकार रही है कि उन्हें बैलाडीला से सिर्फ 10 फीसदी लौह अयस्क की आपूर्ति की जाए। बड़े उद्योगों में मशीनीकरण कंम्यूटरीकरण के चलते मजदूरों की छंटनी व बरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पूंजी निवेश के विलोम अनुपात में रोजगार की उपलब्धता है।

महिलाओं पर अत्याचार बेरोकटोक जारी हैं। इसमें राज्य हिंसा सबसे आगे है। संघर्ष इलाकों में महिलाओं पर अत्याचार को जन दमन के औजार के रूप में सरकारी सशस्त्र बल इस्तेमाल कर रहें हैं। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर, शाला–आश्रम–छात्रावासों में बालिकाओं–युवतियों पर होने वाले अत्याचार कुल मिलाकर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के लिए शोषक–शासक वर्ग व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें ही जिम्मेदार हैं। आर्थिक क्षेत्र में अपने शोषण व लूट को जारी रखने व विरोध की मानसिकता को भटकाने के लिए सामांती कुसंस्कृति व साम्राज्यावादी विषैली संस्कृति को पलने–फूलने व बढावा देने वाली सरकारें जनाक्रोश को ठंडा करने, आन्दोलनों को भटकाने के लिए ही निर्भया जैसे कानून बनाती हैं।

दरअसल ये सरकारें उत्पीडित जनता की मूलभूत समस्याओं को हल नहीं कर सकती। बुनियादी जरूरतों–खाना, कपड़ा, मकान, पेयजल, इलाज, शिक्षा,रोजगार, इज्जत से जीने के अवसर आदि को पूरा नहीं कर सकती हैं। इस शोषण मूलक अर्ध सामांती, अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था में कुछ सुधारों से यह संभव नहीं है। इस शोषण मूलक व्यवस्था का अमूलचूल परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है जो सिर्फ क्रांतिकारी जनयुद्ध के जरिए ही संभव है।

ढोंगी लोकसभा दर असल जन प्रतिनिधियों की सभा नहीं, यह बलवाई, गुण्डों का अड्डा है। यह चुनाव एक नौटंकी है, धोखा है। उसल में यह हर पांच साल या कम–ज्यादा समय में शासक वर्गों का कौन सदस्य जनता को लूटने व उनका दमन करने के बारे में लोकसभा में बैठकर निर्णय लेगा, इसका फैसला करने के लिए ही होता है। यानी वोट डालने या चुनाव में भाग लेने का मतलब है आगामी पांच साल तक अपने शोषण, व दमन करने वाले को चुनना।

लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभाओं में बैठकर ये बलवाई, गुण्डे, अत्याचारी व भ्रष्ट लोग कानून बनाकर जन धन को लूटाते हैं, लूटते हैं, घपले–घोटाले करते हैं, काली कमाई को स्विस बैंकों में जमा करते हैं। और विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने कानून बनाते हैं जैसे यूएपीए, मकोका, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून आदि। यही सब करने इन पर हजारों करोड़ रूपए खर्च किये जाते हैं। 15वीं लोकसभा के 543 सदस्यों में से भाजपा के 44 एवं कांग्रेस के 44, शिवसेना के 9 सहित कुल 162 अपराधिक चरित्र के हैं। राज्य सभा के 232 सदस्यों में से 40 दागी हैं। इनमें से 100 से ज्यादा सदस्यों पर हज्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामलें दर्ज हैं। 15वीं लोकसभा के संचालन के लिए कुल 10 हजार करोड़ खर्च हुए। जन समस्याओं पर वहां चर्चा, हल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

सत्ता की भोगविलासिता की होड़ में ये पार्टियां आपस में लड़–भिड़ती हैं लेकिन जन आन्दोलनों , क्रांतिकारी आन्दोलनों को कुचलने में, प्रगतिशील– जनवादी ताकतों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दबाने में ये सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर एक होते हैं। जनविरोधी नीतियों पर अमल करने में ये एक–दूसरे का बखूबी साथ निभाते हैं। 1967 के नक्सलबाड़ी किसान सशस्त्र संघर्ष से लेकर आज हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध को खत्म करने के शासक वर्गो की रणनीति–कार्यनीति तक तमाम संसदीय दलों में एका है, सत्ताधारी हो या विपक्षी। हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध ही नहीं, जल–जंगल–जमीन व संसाधनों पर अपने हक के लिए संघर्षरत तमाम आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता पर, हमारे संघर्ष इलाकों में ही नहीं, जन संघर्ष के तमाम इलाकों में देश के शासक वर्गो के द्वारा 2009 के बीच से अन्यायपूर्ण युद्ध–आपरेशन ग्रीनहंट थोपा गया है। यह अमेरिकी सेना, गुप्तचर विभाग–एफ.बी.आई के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में, भारतीय सेना के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी से अमल में लायी जा रही विश्वासघाती एल.आई.सी (कम तीव्रता वाली युद्ध नीति) के तहत जारी फासीवादी चौतरफा सैनिक हमला है। इस हमले का हमारी पार्टी, हमारी सेना– पीएलजीए, क्रांतिकारी जनताना सरकारें, जन संगठन व जनता बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं।

650 कंपनियों यानी 72 हजार अतिरिक्त अर्ध–सैनिक बलों सहित कुल 1 लाख 50 हजार सशस्त्र बलों की संगीनों के साये में विगत 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने का चुनाव आयोग ने दावा किया था। जबकि सच्चाई यह है कि चुनाव के दो महीने पूर्व से ही अभूतपूर्व दमन अभियान चलाकर संपन्न कराये गये इन चुनावों का दण्डकारण्य के 700 से ज्यादा गांवों की जनता ने बहिष्कार किया था। दसियों मतदान केंद्रों में एक भी वोट नहीं पड़ा। झूठे लोकतंत्र का बहिष्कार करके यहां की जनता ने सही लोकतांत्रिक पक्रिया के तहत ग्राम सभाओं में चुनी गयी क्रांतिकारी जनताना सरकारों के प्रति अपना विश्वास जताया है। सरकारी सशस्त्र बलों के आतंक का डटकर मुकाबला करते हुए हमारी पीएलजीए ने जनता की सक्रिय भागीदारी से प्रतिरोध अभियान संचालित करके 17 पुलिस जवानों को मार गिराया एवं 20 को घायल किया था। 87 जवान विभिन्न प्रकार के ट्रैपों में फंसकर घायल हो गये थे।

इस बार सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए हजारों अतिरिक्त बलों को लगाया गया है। जनवरी, फरवरी व मार्च महीनों में लगातार गश्त अभियानों को संचालित करते हुए गांवों पर हमले किये गये। लोगों की बेदम पिटाई, सैकड़ों की अवैध गिरफ्तारियां की गयी। कइयों को इनामी माओवादी घोषित कर फर्जी केसों में जेल भेजा गया। बेतकाटी(महाराष्ट्र), नेलनार (नारायणपुर), कांकेर, बीजापुर जिलों में फर्जी मुठभेड़ों में 15 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। आतंकी माहौल कायम करके चुनाव पूरा करवाने की कवायद जारी है।

हमारी पार्टी जनता व जनवादी ताकतों से अपील करती है कि चूंकि कांग्रेस, भाजापा, भाकपा, बसपा, स्वाभिमान मंच, चुनावी मैदान उतरी नयी आम आदमी पार्टी सभी शोषक–शासक वर्गो की सेवा करने वाली पार्टियां ही है, इसलिए किसी के भ्रम में न रहकर चुनावों का बहिष्कार करें। देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस देश की दुस्थिति के लिए

प्रधान जिम्मेदार है। भाजपा फासीवादी, हिन्दू धर्मोन्मादी पार्टी है जो भगवा आंतकवाद को बढ़ावा देते हुए अल्पसंख्यक मुस्लिम व ईसाईयों पर हमलों के लिए मुख्य जिम्मेदार है। हिन्दू धार्मिक एजेन्डे पर कभी खुला व घोषित रूप से तो कभी उसे छुपाकर विकास की दुहाई देते हुए लोगों को भरमाने व भटकाने की कोशिश करती आ रही है।

1951 में ही तेंलगाना किसान सशस्त्र संघर्ष को तिलांजलि देकर भाकपा एक संशोधनवादी पार्टी में तब्दील हो गयी थी। जनता की समस्याओं को लेकर जन संघर्षो को खुले व कानूनी दायरे में बांधकर अपनी संसदीय राजनीति को आगे बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। कम्यूनिस्ट पार्टी के नाम पर यह शासक वर्गो की सेवा ही कर रही है।

एन.जी.ओ की पृष्टभूमि के साथ–साथ गांधीवादी अहिंसा, स्वराज और जेपी का समाजवाद एवं क्रांतिकारी लफ्फाजी का सम्मिश्रण लेकर पुरानी संसदीय पार्टियों से उब चुकी जनता को भरमाने आम आदमी पार्टी नयी कोशिश कर रही है। देश भर में शासक वर्गों, राजनेताओं–अफसरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्यम वर्गीय जनता में जो आक्रोश था उसे भुनाते हुए आप पार्टी आगे आई है। लेकिन शोषण मूलक व भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के बगैर भ्रष्टाचार को खत्म करना न सिर्फ कोरी कल्पना है बल्कि जनता के साथ छल व धोखा ही है।

चुनाव आयोग व चुनावी पार्टियों के हर तरह की कवायद के बावजूद उल्लेखनीय संख्या में लोग मतदान केंद्रों से दूर ही रहते हैं। चुनाव सुधारों के जरिए चुनाव प्रक्रिया के प्रति भरोसा कायम करने व बढ़ाने के तहत इस बार नोटा बटन चालू किया गया है। लेकिन नोटा का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों में भी दसियों हजारों वोटरों ने नोटा दबाया था लेकिन इससे चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पडा है। चुने गये प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की तरह भी नहीं है, यह। इसलिए चुनावी प्रक्रिया को ही पूरी तरह नकारे व वैकल्पिक जन राज सत्ता के अंग– क्रांतिकारी जनताना सरकारों को चुनने की प्रक्रिया से जुड़े।

हमारी पार्टी चार उत्पीड़ित वर्गो–मजदूर किसान, पेट्टी बुर्जुआ, देशी बुर्जुआ (छोटे व मध्यम) की संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में भारत की जनता के नवजनवादी गणराज्यों के फेडरेशन के निर्माण के लक्ष्य से क्रांतिकारी जनयुद्ध को जारी रखी हुई है। यही आज के झूठे लोकतंत्र व वर्तमान फर्जी संसदीय प्रणाली का असली विकल्प है। इस दिशा में कदम बढ़ाने, ऑपरेशन ग्रीन हंट को हराने के लिए जारी जनयुद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाने हम आव्हान करते हैं।

गुड्सा उसेंडी

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)